

तापमान

भोपाल	17.0°	32.0°
इंदौर	17.0°	34.0°
जबलपुर	20.0°	32.0°
ग्वालियर	22.0°	35.0°
सागर	21.0°	34.0°

www.naidunialive.com

राजधानी... भरत यादव ने सचिव जनसंपर्क का कार्यभार ...

खेल... एकदिवसीय में सर्वाधिक छके: धोनी और रोहित शीर्ष ...

व्यापार... शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेस 1534 ...

देश-विदेश... अंतर्राष्ट्रीय फर्टिलिटी ट्रिज्म में फर्जीवाड़ा ...

माँ कात्यायनी



नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। मां कात्यायनी की श्रद्धा भाव के साथ विधिपूर्वक पूजा करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। माता को पीले रंग की मिठाई का भोग लगता है और पूजा में उनके मंत्रों का पाठ भी अवश्य करें।

ख़ास-ख़ाबरेँ

एक नवंबर से फोन पर दिखेगा व्यक्ति का नाम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में 1 नवंबर 2026 से फोन पर कॉल आने पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने रेलीकॉम कंपनियों को यह सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें सिम खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए पहचान पत्र पर दर्ज नाम प्रदर्शित होगा। इस सुविधा से लोगों को फर्जी कॉल पहचानने में मदद मिलने की उम्मीद है।

स्कूल की छत गिरने से 35 की मौत, 40 घायल

पेशावर, पंजाबी: पाकिस्तान के पेशावर में गुरुवार को एक निजी स्कूल की छत गिरने से 35 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 34 छात्र और एक महिला शिक्षिका शामिल हैं। सभी बच्चों की उम्र 13 साल या उससे कम बताई गई है। हादसे के बाद पुलिस ने निजी स्कूल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना पेशावर के दौरा कॉलीनी इलाके में हुई। हादसे में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों के उपचार के लिए अस्पताल में आपतकाल घोषित कर दिया गया है।

नेहा के बयान पर भाजपा ने राहुल गांधी को घेरा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भाजपा ने एआईएसए अध्यक्ष नेहा बोरा के बंगलादेश के युवा आंदोलन पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि नेहा बोरा के शब्दों के पीछे राहुल गांधी की सोच है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक मार्च के दौरान नेहा बोरा को आंदोलन के चेहरे के रूप में पेश किया था।

कोंकरोव जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली के प्रेस क्लब में गुरुवार को कोंकरोव जनता पार्टी (सीजेपी) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामेदार हुई। इसमें वरिष्ठ अधिकता प्रशांत भूषण और अभिनेता प्रकाश राज भी शामिल हुए। प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार की सख्ती जारी रही तो सरकार बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नागरिक समाज और युवाओं के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को कर्नाट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

मप्र और उप्र समेत 17 राज्यों में मतदाता सूची का होगा पुनरीक्षण

एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा जुड़वा सकेंगे नाम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष संधि पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इस प्रक्रिया में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्य शामिल हैं। आयोग के अनुसार, जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां संधि पुनरीक्षण का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना, पहले से दर्ज जानकारी में गलतियां सुधारना और सूची को अद्यतन रखना है। एक जनवरी के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा भी पहले से आवेदन कर सकेंगे। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में राजस्थान चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होगा। वहीं, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होगा। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या और उनके स्थान की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। सामान्य तौर पर एक मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। आवश्यकता के अनुसार नए मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं।

सीजेआई बोले- हमें कोई धमका नहीं सकता

राहुल गांधी समेत 16 नेताओं को नोटिस

गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत को धमकाकर या दबाव डालकर प्रभावित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अदालत के बाहर और भीतर कही जा रही बातों की जानकारी न्यायपालिका को है।

सीजेपी प्रदर्शन मामले में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोंकरोव जनता पार्टी (सीजेपी) के 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मेंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने जंतर-मेंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के फैसले पर भी केंद्र से जवाब मांगा। मामले में प्रदर्शन के दौरान मेट्रो सेवाएं और इंटरनेट बंद किए जाने से जुड़े मुद्दों पर भी सुनवाई हुई। इससे पहले केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में इंटरनेट बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। गृह सचिव गोविंद मोहन ने हलफनामे में कहा था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने का मामला भी सामने आया था। सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिकताओं ने दलीलें रखीं, जबकि केंद्र सरकार का पक्ष सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गौरव भाटिया ने रखा। अदालत ने प्रदर्शन से संबंधित मामलों में पुलिस और अन्य एजेंसियों को सभी संबंधित दृश्य एवं डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ताकि घटनाक्रम की जांच और न्यायिक सुनवाई के दौरान इनका उपयोग किया जा सके।

जंतर-मेंतर पर पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने पर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हिंदू धर्म से गैर-हिंदू धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अपने पुराने सामाजिक दर्जे के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मांग सकता। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मामला तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 के उस फैसले से जुड़ा है, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय और अनुसूचित जाति के लोगों को इस्लाम अपनाने के बाद मुस्लिम पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराया।

जबलपुर-इंदौर आर्थिक कॉरिडोर के लिए बनेगी सरकारी कंपनी

मप्र कैबिनेट के बड़े फैसले, 27,050 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने लगभग 27,050 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें जबलपुर-इंदौर आर्थिक कॉरिडोर के विकास के लिए पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के गठन और खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू करने की स्वीकृति शामिल है। जबलपुर-इंदौर आर्थिक कॉरिडोर विकास कंपनी को 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक चुकता पूंजी दी जाएगी। कंपनी औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्रों के विकास, भूमि प्रबंधन और आंतरिक बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर काम करेगी। मुख्य सड़क और कॉरिडोर का निर्माण इसके कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं होगा। सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए 17 अक्टूबर 2026 तक ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। अधिसूचित मंडियों में बिजली की अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। पात्र किसानों को भावांतर राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। कैबिनेट ने बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,076.37 करोड़ रुपये मंजूर किए। शासकीय स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों और आवासीय खेलकूद भवनों के निर्माण एवं विस्तार के लिए 2,875.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। जनजातीय कार्य विभाग के 94 सांदीपीन विद्यालयों में विद्यार्थियों के परिवहन के लिए 241.88 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। निवाडी, मऊगंज, पांडुप्रा और मैहर में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालयों के लिए 24 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा आयुष महाविद्यालयों और चिकित्सालयों से संबंधित योजनाओं के लिए 3,535 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन के संचालन के लिए 1,697.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए भी 15,557.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।



अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस

28 अक्टूबर तक की मोहलत, भारतीय नागरिकता नहीं होने का हवाला

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनके भारतीय नागरिक नहीं होने और प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। इमरान खान 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हिरासत में लिए जाने का मामला भी सामने आया था। सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिकताओं ने दलीलें रखीं, जबकि केंद्र सरकार का पक्ष सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गौरव भाटिया ने रखा। अदालत ने प्रदर्शन से संबंधित मामलों में पुलिस और अन्य एजेंसियों को सभी संबंधित दृश्य एवं डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ताकि घटनाक्रम की जांच और न्यायिक सुनवाई के दौरान इनका उपयोग किया जा सके।



आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। वह जुलाई में नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। इमरान का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था। उनके पास अमेरिकी नागरिकता और पासपोर्ट है। भारत में रहने और काम करने के लिए वह ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश और रहने से जुड़े नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हिरासत से रिहा होने के बाद इमरान और उनके साथ मौजूद लोगों को पैरल पार्क लाइटना पड़का था। उनकी रिरशेदार लेखा वाशिंगटन ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर दावा किया था कि रिहाई के बाद उन्हें कार या टैक्सी की सुविधा नहीं दी गई। इमरान ने भी हिरासत के दौरान पुलिस वैन में रखे जाने की जानकारी साझा की थी।

लद्दाख को 3350 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात

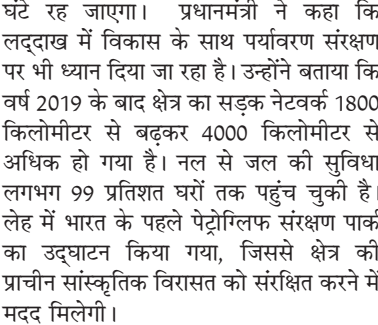
लेह एयरपोर्ट टर्मिनल, निम्पू-पदुम-दारचा सड़क, 40 जलाशय और देश का पहला पेट्रोलिफ संरक्षण पार्क बनेगा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3350 करोड़ रुपये की पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इनमें लेह के कुशोक बकुला रिनपोछे हवाई अड्डे का नया टर्मिनल, निम्पू-पदुम-दारचा सड़क, हानू जलविद्युत परियोजना और 40 जलाशय शामिल हैं। करीब 650 करोड़ रुपये की लागत से बने हवाई अड्डे के नए टर्मिनल से वार्षिक यात्री क्षमता 10 लाख से बढ़कर 35 लाख हो जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा के साथ भू-तापीय तापन तकनीक का उपयोग किया गया है। लगभग 2500 करोड़ रुपये की लागत से बनी निम्पू-पदुम-दारचा सड़क को यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर करीब तीन घंटे रह जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 के बाद क्षेत्र का सड़क नेटवर्क 1800 किलोमीटर से बढ़कर 4000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। नल से जल की सुविधा लगभग 99 प्रतिशत घरों तक पहुंच चुकी है। लेह में भारत के पहले पेट्रोलिफ संरक्षण पार्क का उद्घाटन किया गया, जिससे क्षेत्र की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।



मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम, युवक गिरफ्तार

इलिनॉय, एजेंसी: अमेरिका के इलिनॉय राज्य में नवरात्रि के दौरान हिंदू मंदिर पर हमले की कथित साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने 19 वर्षीय अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह 11 अक्टूबर को ऑर्रोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाने पहुंचा था। आरोपी अपने घर से करीब 65 किलोमीटर दूर मंदिर पहुंचा था। वह अपने साथ राइफल और सैकड़ों गोलियां लेकर आया था, लेकिन हथियार जाम होने के कारण हमला नहीं कर सका। घर लौटने के बाद उसने एक दोस्त को संदेश भेजकर घटना की जानकारी दी और हथियार की तस्वीरें साझा कीं। दोस्त ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान आरोपी के घर से राइफल, भरी हुई मैगजीन और 300 कारतूस बरामद किए गए। उस पर भारतीयों के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणियां करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की बातें कहने के आरोप भी हैं।



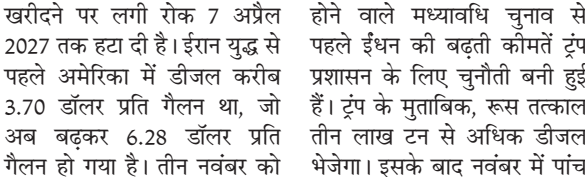
प्रतिबंध ट्रंप तय करेंगे रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध, भारत को छूट मिलने पर भी फैसला उनके हाथ में

भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला!

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने को लेकर अगले 10 दिनों में फैसला ले सकते हैं। अमेरिकी दूत सर्जियो गोर ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत को प्रतिबंधों से छूट मिलेगी या नहीं, इसका निर्णय भी ट्रंप ही करेंगे। अमेरिकी संसद ने 16 सितंबर को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने से संबंधित विधेयक पारित किया था। ट्रंप ने 18 सितंबर को इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक किसी देश पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कानून के अनुसार, इसे पारित होने के 30 दिनों के भीतर इस संबंध में फैसला लेना जरूरी है। गोर ने बताया कि अमेरिकी संसद ने प्रतिबंध लगाने के लिए तीन श्रेणियां तय की हैं। इनमें तेल खरीदना, गैस खरीदना और प्रतिबंधों से बचने में मदद करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों में आने वाले देशों और लोगों की पहचान आंकड़ों के आधार पर की जाती है। भारत भी कई अन्य देशों के साथ इनमें से एक श्रेणी में आता है। अमेरिका में डीजल की कीमतें बढ़ने के बीच ट्रंप ने रूस से डीजल



खरीदने पर लगी रोक 7 अप्रैल 2027 तक हटा दी है। ईरान युद्ध से पहले अमेरिका में डीजल की कीमतें 3.70 डॉलर प्रति गैलन था, जो अब बढ़कर 6.28 डॉलर प्रति गैलन हो गया है। तीन नवंबर को होने वाले मध्यार्वाध चुनाव से पहले ईंधन की बढ़ती कीमतें ट्रंप प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई हैं। ट्रंप के मुताबिक, रूस तत्काल तीन लाख टन से अधिक डीजल भेजेगा। इसके बाद नवंबर में पांच



लाख टन और फिर 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी। आगे चलकर यह मात्रा 30 लाख टन तक पहुंच सकती है। इस बीच, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत भी जारी है। गोर ने कहा कि वार्ता में काफी प्रगति हुई है और बड़े मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। कुछ छोटे मुद्दों पर चर्चा बाकी है। अमेरिका भारत के साथ रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सेंटर और चिप निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। गोर ने भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास का बड़ा केंद्र बनने के लिए उपयुक्त बताया।

